

नौकरी के नाम पर चेहरे की चोरी, बायोमीट्रिक डाटा में सेंध लगाकर टगी

नई दिल्ली, एएनआइ: देश में आनलाइन नौकरी की तलाश का चलन तेजी से बढ़ा है। इसी के साथ साइबर ठगों ने भी धोखाधड़ी के नए तरीके विकसित कर लिए हैं। चेहरे की पहचान, आंखों की स्कैनिंग व निजी दस्तावेज का एआइ के जरिये गलत इस्तेमाल कर लोगों के अति सुरक्षित बायोमीट्रिक डाटा तक पहुंच बनाकर साइबर ठगी की जा रही है। इससे आने वाले दिनों में फर्जीवाड़े व वित्तीय फ्राड के मामले बढ़ने की आशंका के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है।

मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी) की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई (एनसीटीएयू) ने आगाह किया है कि आवेदक अच्छी तरह से पुष्टि के बाद ही इंटरव्यू प्रक्रिया में शामिल हों। शक होने पर तत्काल

▶ फर्जी आनलाइन इंटरव्यू के जरिए चेहरे और आंखों की जानकारी चुरा रहे जालसाज

▶ शक होने पर युवा राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें

▶ आधिकारिक साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत करा सकते हैं

▶ गृह मंत्रालय ने चेताया, जांच परख कर आवेदन करें युवा, हर कदम पर रहें सजग



प्रतीकात्मक

साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर विशेषज्ञों ने युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के दौरान बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है। कहा, अगर कोई कंपनी बिना स्पष्ट कारण

के आधार, बैंक विवरण, चेहरा स्कैन या अन्य संवेदनशील जानकारी मांग रही हो तो सावधान हो जाएं। असली कंपनियां आमतौर पर जल्दबाजी में निजी जानकारी साझा करने का दबाव नहीं बनातीं। गृह मंत्रालय ने कहा, नौकरी का

साइबर जालसाजी की प्रक्रिया

▶ युवाओं को पहले आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता है

▶ उम्मीदवारों से वीडियो इंटरव्यू या आनलाइन सत्यापन को कहा जाता है

▶ सत्यापन में चेहरे और आंखों की स्कैनिंग कराते हैं और डाटा चोरी कर लेते हैं

▶ एआइ की मदद से इमेज प्रोसेसिंग कर बायोमीट्रिक जानकारी की नकल होती है

▶ इसके बाद बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और पहचान संबंधी दस्तावेजों तक पहुंच बनाते हैं

▶ बैंकिंग फ्राड और पहचान चोरी का बड़ जाता है खतरा

प्रस्ताव मिलने पर सबसे पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, ईमेल डोमेन और डिजिटल उपस्थिति की जांच करें। अनौपचारिक ईमेल पते, अधूरी जानकारी या तुरंत प्रक्रिया पूरी करने का दबाव धोखाधड़ी का संकेत हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जवाबदेही तय होनी चाहिए, सरकार बोली-प्रधानमंत्री खुद कर रहे निगरानी

शीर्ष अदालत ने कहा- पेपर लीक बेहद दुखद, हमें युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी पेपर लीक मामले में जवाबदेही पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा, असली समस्या तब तक हल नहीं होगी, जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती। जवाबदेही तभी प्रभावी होगी, जब यह पता हो कि जिम्मेदारी किसके कंधों पर है। कोर्ट ने कहा, ऐसी घटना वास्तव में बेहद दुखद है, हमें अपने युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) और केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। केंद्र की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सरकार युवाओं की चिंता के प्रति गंभीर है और पीएम नरेन्द्र मोदी स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, ताकि कोई कमी न रह जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा, वह हलफनामा दाखिल कर बताए कि ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे सुनिश्चित हो कि 2024 व 2026 की घटनाओं की पुनर्वावृत्ति नहीं होगी। मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में फिर सुनवाई करेगा।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ नीट-यूजी पेपर लीक मामले में दाखिल विभिन्न याचिकाओं

नीट पेपर लीक मामला

- ▶ कहा- यूपीएससी से सीखें, एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ
- ▶ केंद्र सरकार और एनटीए ने कहा, ऐसा दोबारा नहीं होगा

पीठ ने कहा, क्षमता किसी व्यक्ति में नहीं, संस्था में होती है

पीठ ने समस्या को रेखांकित करते हुए कहा, अधिकतर संस्थाएं अस्थायी थीं। कहा, क्षमता व्यक्ति में नहीं, संस्था में होती है। आपको इसी चीज को तैयार करने की जरूरत है। कोर्ट ने दोनों हलफनामों को रिकार्ड पर लेते हुए शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह छह हफ्तों में हलफनामा दाखिल कर बताए कि आगे परीक्षाओं का आयोजन

पर सुनवाई कर रही थी। पेपर लीक होने के कारण नीट-यूजी निरस्त कर दी गई थी और अब 21 जून को दोबारा परीक्षा होनी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर नीट-यूजी कराने वाली संस्था एनटीए व उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति को हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

तुषार मेहता ने बताया कि सरकार गंभीर है और 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए कुछ नए इंतजाम किए



कैसे किया जाएगा। केंद्र यह भी बताया कि किस तरह मानव संसाधन की निरंतरता से संस्थागत स्मृति, विशेषज्ञ कर्मियों की नियुक्ति और संरचना के जरिये संस्थागत विशेषज्ञता व बहुलता स्थापित की जाएगी। कोर्ट ने कहा, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एनटीए के पास सभी भौतिक और बौद्धिक संसाधन उपलब्ध हों।

गए हैं। ये इंतजाम क्या हैं, यह बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे मकसद ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, पीएम खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, ताकि कोई खामी न रह जाए। एनटीए सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं इसके पूर्व चेयरमैन डा. राधाकृष्णन स्वयं कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने समिति की सिफारिशों और उनके अनुपालन का ब्योरा दिया। पीठ ने

राधाकृष्णन से पूछा कि आप समिति के अध्यक्ष थे, क्या आपकी सिफारिशों का पालन हुआ। राधाकृष्णन ने कहा, समिति ने 60 अल्पकालिक व 35 दीर्घकालिक सिफारिशों की थीं और सभी लागू हुई हैं। कोर्ट ने पूछा, अगर सभी सिफारिशें लागू हुई हैं, अनुपालन की निगरानी भी हो रही थी, तो फिर यह स्थिति किस वजह से पैदा हुई। इसका अर्थ है मूल सिफारिश में ही गड़बड़ है, क्योंकि उसमें ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई थी।

इसके बाद कोर्ट ने सालिसिटर जनरल से कहा, अगर ऐसी कोई घटना होती है, तो यह सचमुच बहुत ही दुखद होता है। न सिर्फ छात्रों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी क्योंकि इससे उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। वास्तविक समस्या जवाबदेही की है। जब तक आप उन लोगों की पहचान नहीं कर लेते, जिनका यह दायित्व है, तब तक अस्पष्ट जिम्मेदारी बनी रहेगी। कोर्ट ने एनटीए से कहा, आपको दूसरे संस्थानों से सीखना चाहिए। यूपीएससी का उदाहरण देते हुए कहा, वह हमेशा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा कराती है, वहां कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी। मेहता ने भी सहमति जताते हुए रेलवे की परीक्षा का उदाहरण दिया।

(संबंधित खबरें पेज-5 पर)

देश में जल्द दिख सकते हैं प्लास्टिक के नोट

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारत को जल्द ही पहला प्लास्टिक नोट मिल सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) एक बार फिर से अपने इस सालों पुराने विचार पर आगे बढ़ने जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ा बदलाव होगा। मौजूदा समय में आरबीआइ की तरफ से कागज के नोट प्रिंट किए जाते हैं यह खास प्रकार का पेपर होता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरबीआइ की पटना और मुंबई में हुई पिछली दो बोर्ड मीटिंग के दौरान प्लास्टिक के नोट्स लाने की चर्चा हुई।

इससे पूर्व 2012 में तत्कालीन सरकार ने पांच शहरों (कोच्चि, मैसूरु, जयपुर, भुवनेश्वर, शिमला) में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 रुपये के एक अरब पालिमर नोटों के फोल्ड ट्रायल को

- ▶ अपने 14 साल पुराने प्रस्ताव को रिजर्व बैंक दे सकता है मूर्त रूप
- ▶ कागज की तुलना में टिकाऊ और सस्ते होगी प्लास्टिक की करेंसी



प्रतीकात्मक

मंजूरी दी थी। हालांकि, तकनीकी और परिचालन संबंधी दिक्कतों के चलते इस ट्रायल को रोक दिया गया था। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक

आखिर प्लास्टिक के नोट लाने पर विचार क्यों?

हर वर्ष लाखों नोट खराब होते हैं, जिन्हें चलन से बाहर किया जाता है और बदले में नए नोट छपे जाते हैं जिसकी लागत निरंतर बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआइ का नोट छापने वाला खर्च 6,372.8 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में 5,101.4 करोड़ था। 2024-25 में 23.8 अरब खराब नोट चलन से हटाए गए, जिनकी संख्या 2023-24 में 21.24 अरब थी। हालांकि, 2025-26 में नोट छापने की लागत 4,875 करोड़ रुपये रह गई। हटाए गए नोट की संख्या भी 17.20 अरब रही है।

इन देशों में चल रहे प्लास्टिक के नोट

दुनिया के 60 देश प्लास्टिक नोट का प्रयोग रहे हैं। आस्ट्रेलिया 1998 में प्लास्टिक नोट शुरू करने वाला पहला देश बना। इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रोमानिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम ने भी अपनी मुद्रा में प्लास्टिक नोट शामिल किए।

बार फिर प्लास्टिक के नोट लाने की चर्चा हो रही है। इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला नोट की लागत से जुड़ा हुआ है। दूसरा मुद्रा लंबे

समय तक उपयोग में रहे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही आरबीआइ प्लास्टिक के नोट के पायलट प्रोजेक्ट का एलान कर सकता है। जानकारी के

पालिमर नोट की खास बातें

- ▶ पालिमर बैंक नोट एक पतली और लचीली प्लास्टिक पर प्रिंट किए जाते हैं
- ▶ पालिमर के यह नोट काफी हल्के होते हैं और इन्हें मोड़ा जा सकता है
- ▶ यह नोट काफी मजबूत हैं और इन पर गंदगी-नमी का ज्यादा असर नहीं होता है
- ▶ इनमें सुरक्षा के लिए कई आधुनिक फीचर शामिल किए जा सकते हैं
- ▶ माइक्रो-ऑप्टिक होलोग्राम और खास तरह की स्याही के चलते इनकी नकल करना काफी मुश्किल है
- ▶ प्लास्टिक होने के बावजूद यह क्रेडिट या डेबिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते हैं
- ▶ इन नोटों का इस्तेमाल कागजी मुद्रा की तरह ही किया जा सकता है
- ▶ प्लास्टिक के इन नोटों को लंबे समय तक चलन में रखा जा सकता है
- ▶ लंबे समय तक चलने के कारण बैंकों को इन्हें बदलने पर खर्च कम आता है

अनुसार, पालिमर नोट लाने के पीछे की बड़ी वजह शेल लाइफ भी है। मौजूदा समय में कागज से बने नोट की शेल लाइफ काफी कम होती है।

गांवों में जीवन सुगम बनाएंगे राज्यों के 'ई-गवर्नेंस' माडल

स स ▶ पंचायतीराज मंत्रालय ने दिया मंच, सात राज्यों ने साझा की पहल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

गांवों में जीवन की सुगमता बढ़ाने के लिए जिस तरह से कई राज्यों ने पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस के माडल को अपनाया है, वह अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। पंचायतीराज मंत्रालय ने ऐसी पहल करने वाले राज्यों को मंच देने का निर्णय किया है।

इसी प्रयास में पहला संस्करण शुकवार को गुवाहाटी में आयोजित किया गया, जहां सात राज्यों ने अपने माडल प्रदर्शित किए। केंद्र का प्रयास है कि बेहतर माडल के बिंदुओं का संकलन कर ऐसा माडल प्रस्तावित किया जाए, जिसे अपनाकर सभी राज्य नागरिक सेवाओं की पहुंच धरातल पर बढ़ा सकें।

'सेवा से समृद्धि: पंचायत के नेतृत्व में सेवा प्रदाय' शीर्षक से क्षेत्रीय कार्यशाला का पहला संस्करण आयोजित किया गया। इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साझेदारी में हुए इस कार्यक्रम में असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने-अपने माडल साझा किए। केंद्र सरकार की ओर से पंचायत

ये माडल किए गए प्रदर्शित

● **असम- सेवा सेतु**: घर-घर सेवा प्रदाय, आइटी प्रणाली का एकीकरण और नागरिक अनुकूल माडल

● **राजस्थान- ई मित्र**: एकल खिड़की से अनेक सरकारी सेवाओं की डिजिटल पहुंच

● **पंजाब- ई सेवा**: पारदर्शी और नागरिक केंद्रित सेवा प्रदाय

● **मध्य प्रदेश- लोक सेवा गारंटी पोर्टल**: समयबद्ध सेवा प्रदाय की कानूनी गारंटी

● **आंध्र प्रदेश- पंचायत सचिवालय प्रणाली**: ग्राम पंचायत सचिवालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत सेवा प्रदाय

● **तेलंगाना- मी सेवा**: समावेशी और पारदर्शी तकनीक सक्षम नागरिक सेवाएं

● **ओडिशा- ओडिशा वन और सेवा ओडिशा**: एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म, चौबीसों घंटे नागरिक पहुंच और रीयल टाइम ट्रैकिंग

प्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्राम स्तर उद्यमियों को बताया गया कि यह कार्यशाला पंचायतीराज मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पंचायत के नेतृत्व में शासन को

मजबूत करना और ग्राम स्तर पर नागरिक केंद्रित सार्वजनिक सेवाओं की प्रदाय व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इस पहल का लक्ष्य है कि पंचायतें उत्तरदायी, पारदर्शी व तकनीक सक्षम संस्थान बनें, जो ग्रामीण समुदायों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकें और ग्रामीण भारत में जीवन की सुगमता को बढ़ा सकें।

मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से संस्थाओं द्वारा किए गए सफल सेवा प्रदाय प्रयासों को पहचानकर उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इन्हें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा ताकि वे भी इन्हें अपना सकें। पंचायतीराज राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने कामन सर्विस सेंटरों की महत्वपूर्ण उपयोगिता पर जोर दिया और कहा कि राष्ट्रीय समृद्धि का मार्ग गांवों, किसानों और ग्रामीण आजीविका से होकर गुजरता है। व्यक्तियों का सच्चा सशक्तीकरण ही सशक्त गांवों, सशक्त राज्यों और अंततः एक विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र की नींव है। संयुक्त सचिव मुक्ता शेखर ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 : इंटरनेट चलाने वाली महिलाएं दोगुनी, 33% से बढ़कर 64% हुईं

मोटापा; 27% पुरुष ओवरवेट हैं

NFHS-6: 30.7% महिलाएं और 27.3% पुरुष ओवरवेट यानी मोटापे की श्रेणी में हैं।
NFHS-5: महिलाओं में 24% और पुरुषों में 22.9% मोटापे का शिकार थे।

कारण: जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और अत्यधिक फैट व शुगर युक्त खान-पान की आदतें मोटापे को तेजी से बढ़ा रही हैं।

डायबिटीज; 4 साल में 35% बढ़े

NFHS-6: 17.8% महिलाएं और 20.9% पुरुष हाई या वेरी हाई डायबिटीज से पीड़ित।
NFHS-5: महिलाओं में 13.5% व पुरुषों में 15.6% इस गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे।

कारण: डेस्क जॉब, घंटों स्क्रीन के सामने बैठने और पैदल न चलने से शारीरिक सक्रियता घट रही, जो बड़ी वजह है।

हेल्थ बीमा; 19% परिवार और कवर

NFHS-6: लगभग 60.2% परिवारों के पास अपना कोई न कोई स्वास्थ्य बीमा है।
NFHS-5: पिछले सर्वे के 41.0% के मुकाबले एक बड़ा व सकारात्मक उछाल।

कारण: केंद्र की 'आयुष्मान भारत' व राज्यों (जैसे राजस्थान की चिरंजीवी) की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का असर।

मोबाइल; महिलाएं 10% तक बढ़ीं

NFHS-6: देश की 63.6% महिलाओं के पास अपना मोबाइल, वे खुद चलाती हैं।
NFHS-5: पिछले सर्वे के 53.9% के मुकाबले लगभग 10% की भारी वृद्धि हुई है।

कारण: सस्ते स्मार्टफोन, क्विफायती इंटरनेट डेटा, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल बैंकिंग व सोशल मीडिया उपयोग से बढ़ावा।

घरेलू हिंसा घटी; कामकाजी महिलाएं बढ़ीं

निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी रेट रिकॉर्ड 54% पर, पिछले सर्वे में 47% था

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

पिछले 3-4 साल में देश-समाज की बदलती तस्वीर दिखाने वाले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचए-6) की रिपोर्ट शुक्रवार को जारी हो गई। 2023-24 की इस रिपोर्ट में 101 पैमानों को आंका गया। पिछला एनएफएचए-5 साल 2019-21 में आया था। सर्वे में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ चिंताजनक ट्रेंड सामने आए हैं। महिलाओं में मोटापा पिछली बार के मुकाबले करीब 7% बढ़ गया। निजी अस्पतालों में होने वाली सिजेरियन डिलीवरी की दर 54.1% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो गंभीर है। पिछले सर्वे में 47.4% थी। शुरुआती 6 महीनों तक शिशुओं को 'केवल स्तनपान' कराने की दर 63.7% से गिरकर 55.8% पर आ गई है।

राहत की बात यह है कि देश में घरेलू हिंसा की दर 29.2% से घटकर 22.3% पर आ गई है यानी इसमें 6.9% अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाल विवाह (18 से कम) का कुल आंकड़ा 23.3% से घटकर 20.1% रह गया है। कामकाजी महिलाएं 30.8% तक पहुंच गईं, जो पहले 25.4% थीं। बिजली की पहुंच 98.3% और साफ पेयजल सुविधा 96.5% घरों तक हो गई। सबसे सुखद बदलाव डिजिटल मोबाइल पर दिखा है, जहां महिलाओं में इंटरनेट का उपयोग दोगुना होकर 64.3% पर पहुंच गया है, हालांकि वे पुरुषों (80.5%) से अब भी पीछे हैं। देश के 715 जिलों के करीब 6.79 लाख परिवारों को कवर करने वाला यह सर्वे जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण के संकेतकों पर अहम प्रमाण देता है, जिससे जिला स्तर तक नीतियां बनाने और योजनाएं लागू करने में मदद मिलती है।

भास्कर रिसर्च

बिहार में वैवाहिक हिंसा सबसे ज्यादा; बाल विवाह में प. बंगाल आगे, झारखंड में सबसे कम महिलाएं मोटापे का शिकार हुई हैं...

मद्र: इंटरनेट चलाने वाली महिलाएं ढाई गुना बढ़ीं, अब 92% का छाता

महिलाओं द्वारा इंटरनेट के उपयोग में सबसे क्रान्तिकारी उछाल। NFHS-5 के 26.9% से ढाई गुना बढ़कर NFHS-6 में 62.0% हुआ।
महिलाओं के बैंक खातों के सक्रिय संचालन में 17.4% की वृद्धि (74.7% से 92.1%) दर्ज की गई है। सरकारी योजनाएं बड़ा कारण।

छत्तीसगढ़: 94% महिलाएं घर के फैसलों में सक्रिय भागीदार बनती हैं

घरेलू स्तर पर महिलाओं को आजादी देने में सबसे आगे है। यहां रिकॉर्ड 94.4% महिलाएं पारिवारिक निर्णयों में सक्रिय भागीदार हैं।
आर्थिक आत्मनिर्भरता में भी स्थिति बेहतर है। यहां सबसे अधिक 42.8% महिलाओं को उनके काम के बदले नकद वेतन मिल रहा है।

बच्चों में नाटापन करीब 6% घटा; 2 साल तक के सिर्फ 15% बच्चों को संतुलित खाना मिल पा रहा है

पिछले सर्वे (NFHS-5) में कुपोषित बच्चों में नाटापन का आंकड़ा 35.5% था, जो अब घटकर 29.3% पर आ गया है। बच्चों की लंबाई में आया यह 6.2 प्रतिशत अंकों का सुधार एक बहुत बड़ी और सकारात्मक राहत है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि 6 महीने से 2 साल तक के केवल 15.3% बच्चों को सही और संतुलित खाना मिल पा रहा है। इसका मतलब है कि करीब 85% बच्चों को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा।

देश में कौन-कहां?

सिजेरियन प्रसव: तेलंगाना सबसे खराब बदतर: तेलंगाना (62.2%) और आंध्र प्रदेश (52.2%) में स्थिति सबसे चिंताजनक है।
बेहतर: मेघालय में सबसे कम 6.4%।
बाल विवाह: केरल में सबसे कम होते हैं बदतर: पश्चिम बंगाल (36.4%) और बिहार (34.6%) में सबसे अधिक मामले।
बेहतर: केरल (2.9%), सबसे सुरक्षित।
वैवाहिक हिंसा: हिमाचल में सबसे कम बदतर: बिहार (36.1%) में हालात खराब।
बेहतर: हिमाचल (4.3%) सबसे सुरक्षित।
मोटापा: आंध्र की महिलाएं सबसे आगे बदतर: आंध्र (48%), सिक्किम (48%) केरल (46.7%) की महिलाओं में सर्वाधिक।
बेहतर: मेघालय (13.8%) और झारखंड (16.9%) में यह समस्या सबसे कम है।

राजस्थान: कामकाजी महिलाएं तो 10% बढ़ीं, पर फैसले लेने में पीछे

राजस्थान में महिलाओं के नकद वेतन मिलने की दर में करीब 10% का अच्छा सुधार (17.4% से बढ़कर 26.9%) हुआ है।
घरेलू स्तर पर महिलाओं की निर्णय लेने की भागीदारी में करीब 3% की गिरावट देखी गई है, जो 87.7% से घटकर 84.5% रह गई है।

गुजरात: नकद वेतन पाने वाली महिलाएं करीब 6% बढ़ गई हैं

घर के फैसलों में महिलाओं की हिस्सेदारी 93.5% हुई, जो पिछले सर्वे में 92.2% थी।
नकद वेतन पाने वाली महिलाएं 36.6% हो गईं, जो पिछले सर्वे में 30.8% दर्ज हुई थीं।
खुद मोबाइल इस्तेमाल करने वाली महिलाएं भी 58.8% हो गईं, जो 48.8% पर थीं।

शहर गांव

गांव में प्रति महिला बच्चों का औसत 2, शहर में कम

मकान और/या जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली महिलाओं वाले परिवार बढ़े हैं शहरी: 18.2% परिवारों में महिलाओं के नाम पर (अकेले या संयुक्त रूप से) घर या जमीन।
ग्रामीण: आंकड़ा थोड़ा बेहतर यानी 19.1% है।
कुल: 18.8% परिवारों में महिलाओं के पास संपत्ति का मालिकाना हक है।

तुलना: NFHS-5 के 14.0% के मुकाबले संपत्ति अधिकारों में सकारात्मक वृद्धि हुई है।
परिवार नियोजन का कोई भी आधुनिक तरीका करने वाली महिलाएं घट गई हैं शहरी: आधुनिक तरीके (जैसे गोली, कंडोम, नसबंदी) अपनाते वाली महिलाएं 52.9%
ग्रामीण: यह आंकड़ा 52.7% दर्ज किया गया।
कुल: देश में ऐसी महिलाएं 52.7% हैं।
तुलना: पिछले सर्वे में यह आंकड़ा 56.4% था, यानी इस बार इसमें थोड़ी गिरावट दर्ज की गई।
कुल प्रजनन दर - टीएफआर (प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या) शहरों में कम है शहरी: टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 1.6 रह गया, जो रिप्लेसमेंट लेवल (2.1) से नीचे है।
ग्रामीण: यह रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 पर है।
कुल: कुल प्रजनन दर 2.0 दर्ज की गई है।
तुलना: पिछले सर्वे में भी कुल दर 2.0 थी थी।

NEET leak left students, families traumatised: SC

Top court says paper leak points to 'ad-hocism' and lack of 'institutional memory and framework' within the National Testing Agency; PM is 'personally monitoring' the situation, govt. informs court

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

Students and entire families have been traumatised by the National Eligibility-cum-Entrance Test-Undergraduate (NEET-UG) paper leak case, the Supreme Court said on Friday. The court observed that years of hard work and emotional investment had gone waste even as the Union government said Prime Minister Narendra Modi was "personally monitoring" the situation.

A Bench headed by Justice P.S. Narasimha asked why the National Testing Agency (NTA), which holds the NEET-UG exam, repeats its mistakes when the Union Public Service Commission had so far made none.

The court zeroed in on



The real problem will not stop till there is actual accountability. Not in terms of so and so will be liable, it will be effective when we know which individual shoulders the responsibility. Unless you identify the specific duty-bearers, it will be difficult

SUPREME COURT



"ad-hocism" in the NTA, and lack of "institutional memory and framework". The court directed the Ministry of Human Resource and Development to file an affidavit explaining measures it intends to take to tackle the lack of "physical and intellectual wherewithal" within the NTA.

The NTA maintained that the cancellation of NEET-UG 2026 and the

transfer of the investigation to the Central Bureau of Investigation (CBI) themselves reflected the seriousness with which examination integrity was treated by both the NTA and the Centre.

"It is actually traumatic when something like this happens. Traumatic, not just for students, but for their families too. There is investment of so many

years of emotion and study involved, and gone," Justice Narasimha said.

But the court also struck an optimistic tone, saying the situation was "not beyond us".

"We have some of the best officers heading these institutions. But they get transferred and take their experience and know-how with them. The knowledge is not percolated to the next group of people... It is not the individual who should have the memory, the institution must retain its memories," Justice Narasimha observed.

The cancellation of NEET-UG 2026 had left around 23 lakh candidates facing uncertainty over their academic future.

CONTINUED ON

» PAGE 8

International law, 'optional' for powerful states

Voltaire's famous quip about the Holy Roman Empire – that it was neither holy, nor Roman, nor an empire – has often come to mind when I think about the contemporary state of public international law. For all its lofty aspirations, it is frequently neither truly public, nor reliably international, nor consistently law. It is public only in the sense that it concerns states rather than private actors; international only insofar as sovereigns consent to be bound; and law only to the extent that it can be enforced – an increasingly fragile proposition in a world where power, not principle, is again determining outcomes.

The erosion of an edifice of norms

Over the last century and a half, humanity painstakingly constructed an edifice of norms, treaties and institutions meant to restrain the worst impulses of states. From the Hague Conventions to the Geneva Conventions, from the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), from human rights covenants to arms-control regimes, the international community sought to replace the anarchy of the past with a rules-based order. Yet, in recent years, that order has been fraying at an alarming pace. Across continents and conflicts, states have violated foundational principles with impunity, eroding the credibility of the very system meant to protect global peace and stability.

The most fundamental of these principles is the UN Charter's prohibition on the use of force and its guarantee of the sovereignty and territorial integrity of states. Russia's invasion of Ukraine in 2022 and the U.S.-Israeli war on Iran in 2026 stand as the starkest breaches of this norm in decades: an unprovoked assault on a sovereign state, justified through dubious claims and enforced through overwhelming military might. Both invasions confirmed that the Charter's core promise could be shredded when a powerful state chose to do so.

The U.S. and Russian records are equally deplorable in disregarding the prohibition on force. The 2003 Iraq invasion, undertaken without Security Council authorisation and justified on grounds later proven baseless, remains one of the most consequential breaches of the Charter that set a precedent for Russia's conduct. More recently, the targeted killing of Iranian Supreme Leader Ali Khamenei and the U.S.-Israeli strikes on Iran have raised serious questions about the erosion of the norm against unilateral force. Israel's repeated military operations in Gaza and Lebanon, including large-scale bombardments causing extensive civilian casualties, have also drawn widespread allegations of disproportionate force and violations of international humanitarian law.

The pattern is not confined to major powers. Türkiye's incursions into northern Syria,



Shashi Tharoor

Fourth-term Member of Parliament (Lok Sabha) for Thiruvananthapuram (Congress party), the Chairman of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs and the Sahitya Akademi Award-winning author of 29 books, including 'Pax Indica' (2012) and 'The New World Disorder' (2020)

Azerbaijan's use of force in Nagorno-Karabakh, and Ethiopia's conduct in the Tigray conflict, including cross-border strikes into Sudan, have all arguably breached international norms.

Beyond the use of force, states have violated UNCLOS, one of the most widely ratified treaties in the world. The South China Sea has become a theatre of systematic disregard for maritime law. China's expansive "nine-dash line" claim, rejected by the Permanent Court of Arbitration in 2016, continues to be enforced through militarised artificial islands, harassment of foreign vessels, and coercive coast-guard tactics. The Philippines, Vietnam, Malaysia, and Indonesia have all faced incursions into their exclusive economic zones.

The Strait of Hormuz has witnessed repeated blockades and interdictions. Iran and the U.S. have seized foreign tankers, closed the Strait, and imposed maritime blockades in the region, without clear legal justification under UNCLOS. These actions undermine the principle of freedom of navigation, a cornerstone of global trade and maritime stability.

Brazen actions across the world

International humanitarian law has also suffered grievous violations. In Syria, the Assad regime's use of chemical weapons, indiscriminate bombing of civilian areas, and siege tactics have been extensively documented. Non-state actors such as the Islamic State (ISIS) and various militias have committed atrocities on a massive scale. In Yemen, the Saudi-led coalition and Houthi rebels alike have been accused of targeting civilians, hospitals, and critical infrastructure. In Ethiopia's Tigray region, reports of mass killings, sexual violence, and starvation as a weapon of war have shocked the conscience of the world.

Human rights treaties, too, have been flouted with increasing brazenness. Israel's indiscriminate killing of civilians in Gaza and China's treatment of Uyghurs in Xinjiang – including mass detention, forced labour, and cultural erasure – have been described by several governments and scholars as crimes against humanity. Myanmar's military junta has carried out systematic abuses against the Rohingya and other ethnic minorities, prompting genocide allegations. In Iran, the violent suppression of protests following the death of Mahsa Amini revealed a pattern of extrajudicial killings and torture. Even democratic states have not been immune: the U.S.'s use of torture during the "war on terror", Australia's offshore detention of asylum seekers, and Europe's pushbacks of migrants in the Mediterranean have all raised serious legal and moral concerns.

Arms-control regimes have also weakened. The collapse of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, the erosion of the Open Skies

Treaty, and the uncertain future of the New START agreement have revived fears of a new arms race. North Korea continues to defy UN resolutions with missile tests and nuclear development.

Iran's nuclear programme, once constrained by the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), has allegedly accelerated following the agreement's unravelling. These developments threaten to undo decades of painstaking progress in nuclear restraint.

Environmental law, too, has suffered. States have failed to meet their commitments under the Paris Agreement, with emissions rising and climate targets slipping out of reach. Illegal deforestation in the Amazon, often abetted by state actors, violates international norms on biodiversity and environmental protection. Deep-sea mining, pursued without adequate regulation, threatens fragile marine ecosystems.

There is a vacuum

What ties these disparate violations together is not merely their frequency but their impunity. International law depends on consent, reciprocity, and enforcement through collective mechanisms. Yet, the Security Council is paralysed by geopolitical rivalries; the International Criminal Court faces accusations of bias and lacks jurisdiction over major powers; and treaty bodies often rely on voluntary compliance. In this vacuum, states increasingly act as though power, not principle, determines legality. Thucydides' bleak observation – "the strong do what they can, and the weak suffer what they must" – resonates today with unsettling clarity. When powerful states violate international law without consequence, they signal to others that norms are optional and that might is right. The result is a world sliding back toward the law of the jungle.

This is not merely a philosophical concern. The erosion of international law has tangible consequences: conflicts become harder to resolve, civilians bear the brunt of violence, global commons are degraded, and trust between nations evaporates. The rules-based order, imperfect as it is, remains humanity's best defence against chaos.

The challenge in reaffirming the value of international law is that it requires strengthening multilateral institutions, enhancing accountability mechanisms, and cultivating a global political culture that prizes restraint over adventurism. It also requires recognising that international law is not a panacea but a framework – a set of shared expectations that guide behaviour even when perfect compliance is elusive. Without it, the world risks returning to a state where power alone determines outcomes. And in such a world, it is not only the weak who suffer; ultimately, everyone does.

Imperfect though it may be, the rules-based order remains humanity's strongest defence against chaos

RBI data shows why govt. is concerned about dollars flowing out

India's Balance of Payments stood at a deficit of \$30.8 bn in 2025-26, indicating that total outflows including trade and investments exceeded inflows six fold over the previous year

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

The latest data from the Reserve Bank of India (RBI) shows why the government and the central bank are so concerned about dollars flowing out of the country: the total amount of dollars flowing out of the country exceeded inflows by \$30.8 billion in 2025-26, a more than six-fold increase over 2024-25. This Balance of Payments (BoP) had been a surplus as recently as 2023-24.

The data in the RBI's annual report for 2025-26, released on Friday shows that the BoP deficit grew in 2025-26 because of a sharp fall in net foreign investments into India, which compounded a widening trade deficit. The data for 2025-26 is up to December 31. Further, the deficit in 2025-26 was entirely paid for using the RBI's foreign exchange reserves, denting them significantly.

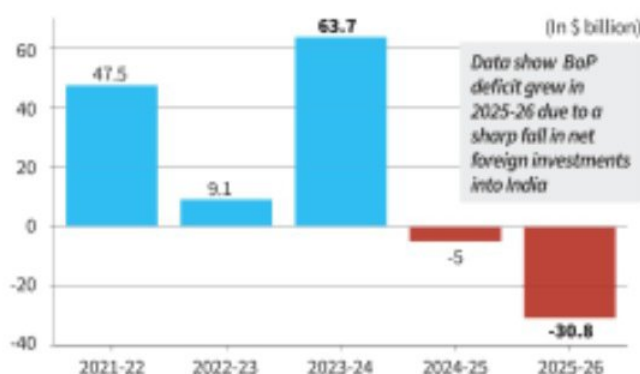
The overall Balance of Payments is a combination of the current account and the capital account.

The current account captures India's trade in goods and services as well as some cross-border financial transactions.

The capital account largely deals with investments, both direct and

Balance of Payments

The outflow of dollars has exceeded inflows by an increasing amount



Source: RBI Annual Report 2025-26 • Note: Data for 2025-26 is provisional. Negative figures indicate a deficit and positive ones denote a surplus.

portfolio, external borrowings, external assistance, and asset transfers.

India generally runs a current account deficit (CAD) since it imports more than it exports. Over the last five years, this CAD has varied significantly, but came in at a three-year high of \$30.2 billion 2025-26. India's overall merchandise trade deficit – the amount that imports exceeded exports – stood \$251.6 billion in 2025-26, down from \$286.9 billion in the previous year.

On the other hand, the surplus on India's 'invisibles' trade, which includes the services trade, fell to \$221.4 billion in 2025-26 from \$263.9 in 2024-25.

In other words, the services surplus shrank more than the merchandise defi-

cit did, meaning that the overall current account saw its deficit widen.

Capital concerns

In 2023-24, when India had a BoP surplus, this was because the surplus on the capital account was so big, it dwarfed the CAD. That is, the CAD was \$26.1 billion in 2023-24, but the capital account surplus was \$89.4 billion. As a result, the BoP surplus was \$63.7 billion.

This scenario did not play out in 2025-26. The capital account surplus that year shrank to \$72 million, down more than 99.5% over the \$16.6 billion seen in 2024-25.

The big reasons for this seems to have been Indians parking their funds abroad and payments related to trade, even though

the financial year 2025-26 included just one month of the ongoing crisis in West Asia. The 'other capital' heading, which includes delayed export receipts, advance payments for imports, and net funds held abroad, stood at a deficit of \$22.6 billion in 2025-26, up from a deficit of \$7.4 billion in the previous year.

The other factor driving the capital account deficit was the outflow of foreign portfolio investments. According to the data, foreign portfolio investors (FPIs) pulled out \$4.3 billion more in 2025-26 than they put in. This reversed the trend of the previous two years where FPI inflows exceeded outflows.

All of this data provides the backdrop for Prime Minister Narendra Modi's exhortation earlier this month for Indians to reduce their fuel consumption and gold purchases. India imports nearly 90% of its oil requirement, and does not produce any gold of its own, although its gold demand is very big.

As a result, a large part of the dollar outflows go in paying for oil and gold imports. The government earlier this month also hiked the import duty on gold and silver to 15% from the previous 6%, and also restricted the import of most kinds of silver.



Ningbo, a port city in southern Zhejiang province, around 200 kilometres south of Shanghai, is a key hub for China's booming Electric Vehicles industry. GETTY IMAGES

Inside China's green transition

Ningbo, in southern Zhejiang province of China, was once a historic maritime hub shaped by Buddhist culture and trade. It has now emerged as a key hub for showcasing China's green industrial push, where electric vehicles, advanced manufacturing, and tightly integrated supply chains are powering the country's bid for global leadership in the technologies of the future. **Ananth Krishnan** reports from the port city

Lying at the foothills of the Mao mountains in southern China, the Temple of King Ashoka is one of the main attractions in Ningbo, a port city in southern Zhejiang province, around 200 kilometres south of Shanghai. Hymns fill the courtyards of the massive temple complex, which is largely empty on a busy weekday.

The temple's history goes back to more than 1,700 years, when it was built during the Western Jin Dynasty. It is one of the 19 Ashoka stupas constructed in China as Buddhism spread. In Ningbo, Buddhist culture, coupled with a long tradition of maritime commerce, has been an important part of the city's history since the 7th century Tang Dynasty, when it emerged as a major port.

Today, the city has emerged at the heart of a different kind of global commerce. It is a key hub for China's booming Electric Vehicles (EV) industry, where new energy automobiles are manufactured in sprawling, modern factories and then exported around the world.

'A future factory'

"The future is our history," reads the sign above the entrance to the factory of Zeekr, a high-end EV brand headquartered in Ningbo and part of Chinese automaker, the Geely Auto Group. Geely also manufactures Volvo Cars, having acquired the company from Ford in 2010, and luxury Lotus autos, after garnering a controlling stake in the British automaker in 2017. EVs have become central to Geely's future. The group sold close to 1.7 million EVs in 2025, a stunning 90% rise from the previous year.

In China, Zeekr is the group's flagship product in this space. Zeekr's cars that roll off the assembly line in Ningbo are transported across China and shipped to Europe and Southeast Asia, its two biggest overseas markets. The Ningbo plant, company representative Zhang Ting says, has been dubbed "a future factory".

It is not hard to see why. The factory floor is a scene out of Star Wars. Automated yellow robotic transports that look like toy cars whizz around the factory floor. One beeps in protest as it brushes up against my feet. Frames of yet-to-be-completed EV cars descend from massive yellow platforms onto the assembly line, where the only humans on site are inspectors checking them for robots. "Around 60-70% of the work is done by robots," Zhang says. There are still some 2,300 people working in this factory, where the EVs are assembled into their final form. The welding factory, also in Zhejiang, is completely autonomous.

A dashboard notes that as of 4 p.m. on a recent afternoon, 366 cars had rolled off the production line, somewhat below the maximum daily capacity of 1,300. The reason, one Zeekr executive explains, is an intended nimbleness. The quick turnaround time allows the company to follow a model where it only manufactures cars for which it has already received a confirmed order.

Zeekr's "future factory" was the result of a 10 billion RMB (\$1.47 billion) investment. At every turn, the emphasis is on "green". One live dashboard measures the factory's carbon footprint at any given minute, including the electricity and water use per vehicle, and the savings from a

Meaningful competition lies in capabilities, technology, and systems. It is not only about price

HE XIAOPENG
Founder, Xpeng Motors

waste heat recovery system designed to be energy-efficient. This year, the savings have so far amounted to the equivalent of the annual gas consumption of 736 Chinese households.

On top of the 'green charts'

Going green appears to have become an obsession in Zhejiang, a province in China's southern manufacturing heartland that played a key role in the country's reform and opening period starting in the 1980s.

Wang Hao, an official from the provincial government, reels off statistics showing the province at the top of China's "green charts": Zhejiang's PM 2.5 particulate air pollution fell last year to an average slightly under 25 – "like Europe," says another official. Last year, the province notched two other landmarks: renewables, for the first time, accounted for 50% of total installed energy capacity; and 100% of the surface water met national standards, following a massive campaign to crack down on industrial waste.

Across the city from the sleek Zeekr factory is a symbol of Ningbo's past – the towering smoke stacks of the Ningbo Iron and Steel Company, or Ninggang, one of China's oldest and biggest steel producers. Local officials cite the company's story as a snapshot of China's green transition – and how Beijing spent billions in overhauling older polluting industries and holding them to stricter emission standards.

At Ninggang, around 4 billion RMB (\$588 million) was spent on "more than 100 emission renovation projects," says Yang Zhenzhu, a representative of the company. Many of these were aimed at reducing emissions and more efficiently recycling the waste water from steel production. Today, the company hosts visitors from companies around China, who come to study it as a model of change.

The first stop on the Ninggang tour for visitors, who are separated from burning hot furnaces carrying golden, molten iron by thin glass walls, is an elaborate water treatment arrangement. All of the water that is used is recycled, coming from the city's major wastewater treatment plant. This water is piped to Ninggang's own treatment station for further treatment, and the excess is desalinated and reused. Zero solid waste is allowed to leave the factory. Waste containing iron and carbon is treated at another

treatment facility and reused.

Pollution remains a serious problem in China. Even in Beijing, despite the undeniable progress – "airpocalypse" days that were regular in the winters of Beijing a decade ago are now far less common – maintaining clean skies is a continuing battle. One clear takeaway from Zhejiang is that the green transition neither came easily, nor for free. Indeed, it required serious and sustained investment on the one hand, and no-nonsense policing and enforcement on the other.

Corruption is rarely spoken of in the context of pollution. Yet, Chinese officials often point to how, in the past, lax enforcement was a huge challenge. Bribes to local officials to look the other way were a common phenomenon. But a crackdown on corruption over the past decade has changed that. It is much harder for polluting factories to pay their way out of punishments for violating standards, while "big data" is being deployed to track factories in real time.

If investment and enforcement have been two key pillars of China's green transition, technology is a third. Chinese companies making EVs, batteries, and solar panels are in an apparent unending race to come up with technologies that are more efficient and cheaper. Technology, more than cost, explains China's dominance of the global EV market, says He Xiaoping, who is the founder of another Chinese EV player, Xpeng Motors, a competitor of Zeekr's. "Meaningful competition lies in capabilities, technology and systems. It is not only about price," he says.

China accounted for around 60% of all global EV sales, according to the International Energy Agency's (IEA) Global EV Outlook 2024. Its dominance in batteries is starker, with China controlling 76% of global lithium-ion battery cell manufacturing, giving its firms a major cost advantage, according to Bloomberg data. Solar photovoltaics are a similar story. To give a sense of the scale, China in 2023 commissioned as many PVs as the rest of the world did, estimated the IEA. China's overwhelming presence in the critical minerals industry underpins its dominance of supply chains, with the country processing 90% of rare earth elements, and 60-70% of lithium and cobalt, which are key for manufacturing batteries.

Indeed, China's proposition to the world is "a complete supply chain", says Qian Zhimin, who is Deputy Director of China's Committee on Pop-



The fact is that energy security and green transition is not a binary choice for us but a strategic pathway on which both complement each other.

QIAN ZHIMIN
Deputy Director of China's Committee on Population, Resources and Environment.

ulation, Resources and Environment.

For Chinese policymakers, the ongoing crisis in West Asia has only further driven home the urgency of green transformation and the advantages of diversifying energy sources. "Today, energy security and green transition are converging," Qian says. "The recent tensions (in West Asia), and the tensions we are seeing in maritime routes like the Strait of Hormuz, mean traditional energy systems continue to face strong external shocks. So green transition is now a practical choice to enhance energy security and self-reliance in a complex external environment. And China offers a complete supply chain."

Impact on the world

If China sees its "complete" supply chain as a strategic advantage, for the rest of the world, dependence on China in these industries of the future is a cause for concern. China's cost competitiveness and technological edge may be enablers of green transformations, but the other side of the equation is the enormous impact of Chinese imports on companies in these sectors around the world that are struggling to stay afloat. The European Union (EU) is a case in point.

The EU, along with Southeast Asia, has more than any other region opened up to Chinese EV and renewable energy companies. China's exports, warned a February 2026 report from an advisory body to the French government, were "affecting the core of Europe's industrial strongholds: automotive, batteries, industrial equipment, chemicals, and others."

"On average, nearly a quarter of European exports is currently exposed to Chinese competition that we deem critical," it said. "On the domestic market, up to 55% of European manufacturing output could be threatened over the medium term if current trends persist. This proportion varies significantly across countries: it reaches around 70% in Germany, 60% in Italy, 50% in Spain and 36% in France," the report added, noting that in 2024, the EU imported €11.1 billion worth of solar panels, €2.9 billion of liquid biofuels, and €0.5 billion worth of wind turbines from extra-EU countries, totalling about €14.5 billion in imports of green energy products. China accounted for 98% of these imports.

Fearing the prospect of "accelerated deindustrialisation", the report said the cost gap estimated by European companies with regard to China was 30-40%. It cited PVs as an early indicator of what may come in other sectors. Since the mid-2000s, when China began massive investments in solar, its growth had led to "a near-monopoly situation for China in photovoltaics" with market share "exceeding 80% across all segments of the value chain."

Leadership on climate change

For much of the Global South, however, China is seen as offering the prospect of an affordable green transformation – a proposition that, many countries note, the West has been unable to compete with, even as the U.S. withdraws from global leadership on climate change.

"China is a leader in this area not for no reason," said Fazel Najeeb, who is the Maldives Ambassador in Beijing and was recently in Ningbo along with the country's Minister of State for Climate Change, Environment and Energy, Mohamed Faiz, at a Shanghai Cooperation Organisation green forum convened by China, reflecting its global ambitions in the sector. "China's leadership is undeniable, whether or not others are withdrawing from issues such as climate change that have a huge bearing on countries like us."

The Maldives, for instance, is clear about seeking opportunities from China, including for its landmark RasMala project, an initiative pushed by President Mohamed Muizzu, which envisages building a zero-carbon safe island on 1,153 hectares of reclaimed land.

Najeeb says, "We are requesting China to work with us to make this island a future city powered by renewable energy entirely, with electric cars and no fossil fuels. Right now, we spend around 33% of our GDP on fossil fuels. We would like to change this."

Maldives is among the many countries in the midst of energy shortages. The Iran crisis, Qian notes, has driven home the lesson that renewable energy "reduces vulnerability to fluctuations in international oil price and enhances economic resilience." He points out that coal still accounts for 52% of primary energy consumption in China and 56% in India. "The fact is that energy security and green transition is not a binary choice for us," he says, "but a strategic pathway on which both complement each other."

ananth.krishnan@thehindu.co.in

